साप्ताहिक
Live not just breaTHE

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

# दि कार्मिक पोस्ट

वर्ष : 5, अंक : 44 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 24 जून से 30 जून 2020 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

# वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में 2.8 डिग्री वृद्धि होकर रहेगी

**कोविड -19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए 60 दिनों के लॉकडाउन में कुछ अच्छे परिणाम मिले। हमने देखा कि नदियां स्वच्छ थीं, जंगली जानवर एवं पक्षी बिना किसी डर के शहरों में घूमते पाए गए और आकाश भी सचमुच नीला था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही हमने ऊर्जा का उपभोग करना बंद किया, हमारे द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले कार्बन की मात्रा में भी कमी आई।**

*कार्बन ब्रीफ द्वारा ईंधन की खपत के विश्लेषण के अनुसार, लॉकडाउन के फलस्वरूप भारत में लगभग चार दशकों में पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई। विश्लेषण के अनुसार, मार्च 2020 की तुलना में अप्रैल 2020 में उत्सर्जन में 30 फीसदी की गिरावट आई। हालांकि यह जलवायु के लिए अच्छी खबर की तरह लग सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। जलवायु नीति का लक्ष्य विकार्बनीकरण के माध्यम से लाभ लेना है और किसी आर्थिक दुर्घटना के फलस्वरूप उत्सर्जनों में आई कमी इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं है।*

*ग्रीन रिकवरी काफी हद तक सरकारी नीतियों पर निर्भर होगी और हम इसका एक नमूना देख भी चुके हैं। 13 मई को, वित्त मंत्री ने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को 90,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की, जिससे वे बिजली उत्पादकों को उनका बकाया भुगतान कर सकें। इस मोर्चे पर, कम से कम, सरकार ने विशेषज्ञों की सिफारिशों का पालन किया है (चाहे अधिसंख्य अन्य मोर्चों पर सरकार ने अपनी मनमानी ही की हो), जो देश के सबसे कमजोर लोगों को सीधे प्रभावित करते हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को पूंजी का प्रबंध करने में दिक्कतें आ रही थीं और उन्होंने इस कदम का उत्साह के साथ स्वागत किया गया। ऐसा तब हुआ जब इस प्रोत्साहन पैकेज में अक्षय ऊर्जा से संबंधित कुछ भी नहीं है।*

*इस पैकेज में 90,000 करोड़ की इस राशि के इस्तेमाल को लेकर शर्तें होनी चाहिए थी, खासकर अक्षय ऊर्जा जेनरेटरों का भुगतान समय पर करने के बारे में। हम जानते हैं कि इस आकार का पैकेज प्रदर्शन को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, स्मार्ट मीटरिंग का विस्तार और वितरण के नुकसान को कम करने की शर्तें इस पैकेज से जुड़ी हैं। ये लक्ष्य महत्वपूर्ण अवश्य हैं लेकिन इनके अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे पुराने थर्मल पावर प्लांटों को बंद करना (खासकर वैसे प्लांट जो चार दशकों से भी पुराने हैं), एक ऐसा काम जो इस पैकेज के माध्यम से संभव था।*

*इस तरह के किसी भी बंद को जस्ट ट्रैन्जिशन के जलवायु मापदंडों का पालन करना होगा। पैकेजों में बंद के तकनीकी पहलू के अलावा उसके मानवीय पहलू पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे आजीविका और आर्थिक नुकसान की भरपाई।*

# वैज्ञानिकों ने बनाई 'पेपर चिप्स', जंगल में आग के फैलने से पहले देगी चेतावनी

**वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई पेपर आधारित चिप बनाई है, जो जंगल में आग के फैलने से पहले ही उसकी चेतावनी दे देगी। पेपर आधारित यह चिप अपनी ही ऊर्जा से चलती है।जिस वजह से इसके लिए बैटरी या अन्य किसी ऊर्जा के स्रोत की जरूरत नहीं पड़ती है।**

हाल ही में अमेज़न के वर्षा वनों और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लगी थी। अनुमान है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से करीब 1.1 करोड़ हेक्टेयर (110,000 वर्ग किलोमीटर) में फैला जंगल, झाड़ियां और पार्क सब जलकर नष्ट हो गए थे। जबकि ब्राजील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च (आईएनपीई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2019 में अमेज़ॅन के जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं में करीब 30 फीसदी की वृद्धि हुई है। 2019 में करीब 89,178 बार आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं।

भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी जंगल की आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आग के फैलने से पहले ही उसपर काबू पाना बहुत जरुरी है। यह तभी मुमकिन हो सकता है कि जब सही समय पर उसका पता चल जाए। पर अधिकांशत: जब तक इस बात का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आग विकराल रूप ले चुकी होती है। जिसपर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। इसने इस कमी को उजागर कर दिया कि जंगलों में बार-बार लगने वाली इस आग को रोकने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली बहुत जरुरी है। वर्तमान में इस दावाग्नि को रोकने के लिए इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट, वॉचटावर और हवा से निगरानी करने जैसे उपाय किये जा रहे हैं। लेकिन यह जब तक इस बात की जानकारी देते हैं। तब तक बहुत देर हो जाती है। पर अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चिप तैयार करने में सफलता हासिल की है जो आग लगने की शुरुवात होते ही इस बारे में जानकारी सिग्नलों के माध्यम से प्रसारित कर देगी। पेपर आधारित यह चिप अपनी ही ऊर्जा से चलती है और इसके लिए किसी प्रकार की बैटरी और ऊर्जा के अन्य स्रोत की जरुरत नहीं पड़ती है। इससे जुड़ा शोध जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ है। इससे पहले भी वैज्ञानिकों ने जंगल में सेंसर के एक नेटवर्क को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। जो तपमान, धुंए और आद्रता में हो रहे बदलावों का पता लगा सके और उसके बारे में जानकरी भेज सके। पर ऐसा संभव नहीं हो पाया था क्योंकि इन सेंसर्स को चलने के लिए बैटरी या अन्य ऊर्जा की जरुरत पड़ती है। जो थोड़े समय के बाद ख़त्म हो जाती है ऐसे में उन्हें फिर से बदलना पड़ेगा। इसके साथ ही अब तक जो सेंसर को बनाने के लिए सामग्री खोजी गई थी वो महंगी और पर्यावरण के प्रतिकूल थी।

## कैसे काम करता है यह सेंसर

लेकिन इस पेपर आधारित थर्मोइलेक्ट्रिक सेंसर बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने दो आयनिक लिक्विड मैटेरियल को चुना है जो तपमान के बढ़ने के साथ ही अलग अलग तरह से बर्ताव करने लगते हैं। उनमें से एक गोल्ड इलेक्ट्रोड की सतह पर अवशोषित कर लिया जाता है जबकि दूसरा उसके विपरीत प्रतिक्रिया करता है। वैज्ञानिकों ने प्रत्येक आयनिक लिक्विड को गोल्ड के दो इलेक्ट्रोड के बीच एक स्याही की तरह जमा कर दिया। जिन्हें एक साधारण पेपर पर लगा दिया गया।

जब इन दो आयनिक लिक्विड मैटेरियल को एक श्रृंखला में जोड़ा गया, तो पता चला कि तापमान में बड़ा अंतर आने पर यह एक विद्युत संकेत उत्पन्न करते हैं। जैसा की आग लगने के मामले में होता है। इसकी जांच के लिए वैज्ञानिकों ने इन्हें घर में लगे एक पौधे पर टैस्ट किया। जब जलते हुए कॉटन को पौधे की जड़ के पास लाया गया तो इससे सेंसर की निचली सतह का तापमान बढ़ गया और उसने एक सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। इस सिग्नल को एक कंप्यूटर माइक्रोचिप की मदद से रिसीवर को भेज दिया गया। जैसे ही यह सिग्नल रिसीवर को मिला उसमें एक अलार्म और लाल बत्ती अपने आप ही सक्रिय हो गए। जो स्पष्ट रूप से आग लगने की चेतावनी देते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार उनके बनाये यह थर्मोइलेक्ट्रिक पेपर चिप्स पर्यावरण के अनुकूल हैं। साथ ही इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनका बैटरी के बिना भी चलना और सस्ता होना है। जिस वजह से इन्हें आसानी से उपयोग किया जा सकता है।

# कोरोनावायरस से अक्षय ऊर्जा की तेजी थमेगी, लेकिन रुकेगी नहीं

हाल ही में तेजी से विकसित होने की उम्मीद कर रहे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के उद्योगों को कोरोनावायरस संक्रमित बीमारी कोविड-19 महामारी से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से आर्थिक संकट बढ़ा है। साथ ही, तेल की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

यह आर्थिक संकट कितना बड़ा होगा और इसका पर्यावरण के साथ-साथ नीतियों पर क्या असर पड़ेगा, यह आकलन करना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति, जिसने वाल स्ट्रीट में ऊर्जा नीति के लिए काम किया हो और शिक्षा, उद्योग व सरकार से जुड़ा हुआ हो को लगता है कि अगले कुछ वर्षों के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा या उससे बेहतर होगा। इन दिनों आर्थिक गतिविधियों के ठप होने से बिजली की मांग कम हुई है, क्योंकि हर तरह की आर्थिक गतिविधियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर बिजली की जरूरत होती है। 2008-09 की आर्थिक मंदी के बाद भी अमेरिका में अगले दस साल तक बिजली की मांग में गिरावट दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, बिजली की बिक्री में 2008 से लेकर 2018 तक कोई खास वृद्धि नहीं देखी गई। 27 मार्च 2020 को अमेरिका में बिजली की खपत 27 मार्च 2019 के मुकाबले तीन फीसरी कम रही। ऐसा पिछले तीन साल से हो रहा है। आर्थिक संकट के बावजूद बिजली का उत्पादन कुछ जगह निरंतर होता है, जैसे कि घरों या अस्पतालों में, जिससे उसका उत्पादन तो नहीं घटना, लेकिन उत्पादन कम होने के कारण इसमें प्रतिशत के आधार पर खासी गिरावट होती है। इससे बिजली उद्योग का राजस्व भी कम होता है, क्योंकि बिजली से चलने वाले उद्योगों में उत्पादन कम हो जाता है और वे बिजली की खपत कम कर देती हैं, बल्कि बिल का भुगतान भी नहीं करती। आर्थिक हालातों की वजह से बिजली की मांग में कमी दुनिया भर में होगी, जिससे नए अक्षय ऊर्जा संस्थानों को नुकसान हो सकता है। बिजली का इस्तेमाल करने वाले संस्थान अपना बजट कम कर देंगे और अपने नए प्लांट नहीं लगा पाएंगे। सोलर सेल, विंड टरबाइन और अन्य हरित ऊर्जा तकनीक बनाने वाली कंपनियों को अपने ग्रोथ प्लान बदलने होंगे। उदाहरण के लिए, मॉर्गन स्टेनली ने 2020 की दूसरी तिमाही में 48 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 28 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 17 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है। लेकिन कुछ दूसरे कारक हैं, जिनकी वजह से यह गिरावट कम हो जाएगी। ऐसा कम से कम अमीर देशों में तो होगा ही। अक्षय ऊर्जा के कई ऐसे प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, जो केवल बढ़ती मांग की वजह से नहीं लग रहे हैं। क्योंकि राज्यों ने स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए कायदे-कानूनों में बदलाव भी किया है। यही वजह है कि कई प्लांटों का निर्माण पहले ही चालू हो चुका है। सरकारी नीतियों और जनता का दबाव है कि कोयले से चलने वाले पावर प्लांट बंद किए जाएं। 2010 में 1,02,000 मेगावाट क्षमता के कोयले से चलने वाले प्लांटों को बंद कर दिया गया था, जो अमेरिका की तब की कुल उत्पादन क्षमता का एक तिहाई था। और 2025 में 17,000 मेगावाट क्षमता के कोयले से चलने वाले प्लांट बंद हो जाएंगे। इनकी जगह हवा, सौर और पन बिजली संयंत्र ले लेंगे। अमेरिका में बिजली उत्पादन न्यूनतम कार्बन ईंधन की ओर बढ़ रहा है, इसलिए कोयले को हटा कर प्राकृतिक गैस और अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

## स्वच्छ ईंधन जरूरी

वतर्मान संकट के बावजूद इनवायरमेंटल इम्पैट असेसमेंट (ईआईए) का दबाव है कि कार्बन मुक्त ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाया जाए। लगभग 50 अमेरिकी कंपनियों ने पहले ही यह वादा किया है कि वे कार्बन उत्सर्जन कम करेंगी, इनमें से 21 कंपनियों ने 2050 तक कार्बन मुक्त होने की शपथ ली है। पिछले साल कई अमेरिकी कंपनियों ने स्वैच्छिक तौर पर हरित ऊर्जा की खरीद बढ़ाई है, जो लगभग 9300 मेगावाट है और यह अमेरिका की कुल बिजली क्षमता का एक फीसदी है। वहीं कई घरेलू उपभोक्ताओं ने भी अलग-अलग विकल्पों से अक्षय ऊर्जा की खरीददारी बढ़ाई है। इनमें से एक विकल्प सामुदायिक सौर ऊर्जा कार्यक्रम है।

## गंदा ईंधन कब तक?

2019 की शुरुआत में ही कच्चे तेल की कीमतें लगभग 64% घट गई । तेल बाजार गुरु डैनियल येरगिन बताते हैं कि यह गिरावट और लंबे समय तक रहने वाली है। तेल कीमतों में गिरावट से अमेरिका की प्राकृतिक गैस की कीमतें भी कम हो जाएगी। आर्थिक गतिविधियां घटने से बिजली और तेल की तरह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल भी कम हो जाता है। आम तौर पर, सस्ती प्राकृतिक गैस, जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने में होता है से बिजली की खपत बढ़ती है और इससे आर्थिक प्रगति होती है, लेकिन इस असामान्य दौर में तेल और गैस की कम कीमतों का अक्षय ऊर्जा पर कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। कुछ जगहों पर अक्षय ऊर्जा के नए प्लांट लग रहे हैं और इनसे तेल व गैस के मुकाबले सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए डीजल से बनने वाली बिजली के मुकाबले सौर ऊर्जा से बिजली की कमी दूर किया जा रहा है और यह सस्ती भी पड़ रही है। खासकर विकासशील देशों में ऐसा देखने को मिल रहा है, जहां सस्ती बिजली की मांग ज्यादा है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी की कमी रहती है और उन्हें बिजली पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। यदि ये देश पैसा बचाने के लिए अक्षय ऊर्जा की बजाय जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं तो वह न केवल जलवायु नीति के लिए खराब होगा, बल्कि इससे वायु प्रदूषण भी बढ़ेगा। यही वजह है कि केंद्रीय बैंक अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने के लिए कम या बिना ब्याज दर पर लोन भी मुहैया करा रहे है, जिनकी पूंजीगत लागत तो अधिक है, लेकिन स्थापित करना सस्ता है। इस मकसद देशों को जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से रोकना है।

## पार्ट्स की कमी

वर्तमान कोरोना महामारी के दौर में अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। इस उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस की वजह से उनके श्रमिक बीमार हो सकते हैं या लॉकडाउन की वजह से उनको उद्योग बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के ज्यादातर पार्ट्स चीन से आते हैं। खासकर एशिया के देश तो चीन पर ही निर्भर हैं। जहां फिलहाल कोरोनावायरस की वजह से सामान नहीं आ रहा है। इस वजह से भारत और आस्ट्रेलिया में कई सोलर प्रोजेक्ट्स में देरी होने की संभावना है।

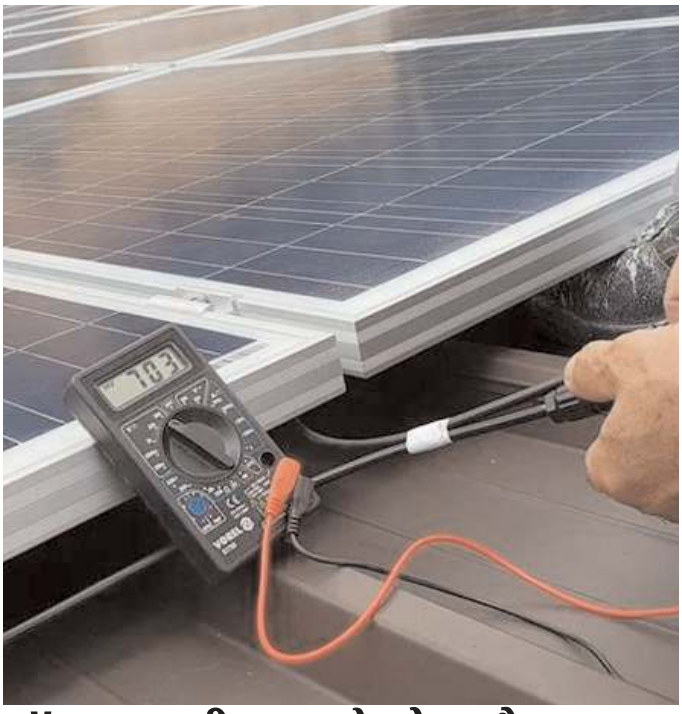

# लॉकडाउन की वजह से सोलर पैनल तक पहुंची 8.3 फीसदी ज्यादा धूप- स्टडी

**नईदिल्ली। दिल्ली में कोरोनावायरस के कारण जो लॉकडाउन किया गया उससे न केवल हवा की गुणवत्ता में सुधार आया है, साथ ही इसके कारण सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। यह जानकारी सेल प्रेस जर्नल जूल में छपे एक नए अध्ययन से पता चली है।**

शोधकर्ताओं के अनुसार लॉकडाउन की वजह से दिल्ली ही नहीं दुनिया के अन्य हिस्सों में भी हवा की गुणवत्ता में सुधार आया है। अनुमान है कि इसकी वजह से दिल्ली में सोलर पैनल तक करीब 8.3 फीसदी ज्यादा सूर्य की किरणें पहुंच पायी, जिसके कारण सौर ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

जर्मनी के हेल्महोल्त्ज़-इंस्टीट्यूट एर्लांगेन-नूर्नबर्ग से जुड़े शोधकर्ता और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक इयान मारियस पीटर्स ने बताया कि, दिल्ली, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। जिस तरह से इस महामारी को रोकने के लिए अचानक से कठोर कदम उठाए गए और लॉकडाउन लागू किया गया। उससे वायु प्रदूषण में भी एकाएक कमी आ गई, जिसका आसानी से पता लगाया जा सकता है।

पीटर्स और उनके सहयोगियों ने इससे पहले भी दिल्ली सहित अन्य शहरों में एक अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने यह समझने का प्रयास किया था कि धुंध और वायु प्रदूषण के कारण जमीन तक पहुंचने वाली धूप पर कितना असर पड़ता है। इसके साथ ही सोलर पैनल और सौर ऊर्जा के उत्पादन पर वायु प्रदूषण का कितना असर पड़ता है।

इस शोध से पता चला है कि मार्च 2020 में 2017 से 2019 की तुलना में 8 फीसदी से ज्यादा विकिरण जमीन तक पहुंचा था7 शोधकर्ताओं के अनुसार इस बीच धरती तक पहुंचने वाला विकिरण दोपहर में 880 वाट प्रति स्क्वायर मीटर से 950 वाट प्रति स्क्वायर मीटर तक पहुंच गया था7 जिसके पीछे की बड़ी वजह वायु प्रदूषण में आई गिरावट थी7

वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास है कि इस शोध से मिले आंकड़ों और पहले के निष्कर्षों कि मदद से सौर ऊर्जा पर वायु प्रदूषण के असर को समझने में मदद मिलेगी7 इसके साथ ही शोधकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि केवल दिल्ली में ही नहीं जहां भी लॉकडाउन की वजह से हवा साफ हुई है, वहां सौर ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि हुई होगी।

पीटर्स के अनुसार यह महामारी कई मायनों में बहुत नाटकीय रही है। दुनिया पहले जैसी नहीं रही, जब तक यह महामारी खत्म होगी, बहुत कुछ बदल चुका होगा7 इसने हमें एक मौका दिया है कि हम देख सकें की साफ हवा में दुनिया कैसी दिखती है7 इसने हमें एक मौका दिया है कि हम तेजी से बढ़ते तापमान को रोक सकें और क्लाइमेट कर्व को फिर से समतल कर सके। इसमें सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जिसकी मदद से ने केवल तापमान में हो रही इस वृद्धि को रोका जा सकता है। बल्कि साथ ही इससे वायु प्रदूषण में भी कमी आ सकती है। जिसकी मदद से हम फिर से खुले नीले आसमान और साफ हवा में सांस ले सकते हैं।

# विकास की कीमत पांच साल में 72,685 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग बदला

पिछले तीन दशकों में जहां दुनियाभर में वनों का क्षेत्रफल कम हुआ है, वहीं वनों के नुकसान की दर टिकाऊ प्रबंधन के विकास के कारण घटी है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट (एफआरए) 2020 के अनुसार, 2015-20 में वनों की नुकसान की अनुमानित दर 10 मिलियन हेक्टेयर रही जबकि 2010-15 में यह दर 12 मिलियन हेक्टेयर थी। एफआरए 2020 संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा 13 मई 2020 को जारी किया गया था। इसमें 236 देशों में 1990-2020 के दौरान वनों से संबंधित 60 कारकों के जरिए वनों की स्थिति और ट्रेंड्स की पड़ताल की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 1990 से दुनियाभर में 178 मिलियन हेक्टेयर वन कम हुए हैं।

वनों को पहुंचा यह नुकसान लीबिया के क्षेत्रफल के बराबर है। हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि 1990-2020 के बीच वनों की शुद्ध नुकसान दर कम हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ देशों में पेड़ों की कटाई में कमी आई है और पौधारोपण के जरिए वन क्षेत्र बढ़ा है। भारत में हजारों हेक्टेयर वन भूमि विभिन्न विकास परियोजनाओं को हस्तांतरित हुई है। पिछले पांच सालों में 69,414.32 हेक्टेयर वन भूमि गैर वन कार्यों के लिए दी गई है। यह जानकारी खुद केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 20 मार्च 2020 को संसद में दी। परिवेश वेबसाइट बताती है कि 2014-15 से 2018-19 के बीच वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 69,414.32 हेक्टेयर भूमि 3,616 परियोजनाओं को दी गई है। मंत्रालय की अन्य वेबसाइट ईग्रीन दूसरी तस्वीर पेश करती है। इसके अनुसार, इस अवधि में कुल 72,685 हेक्टेयर वन भूमि गैर वन गतिविधियों के लिए हस्तांतरित हुई है।

ईग्रीन वेबसाइट 2009 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद बनाई गई थी ताकि राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रतिपूरक वनीकरण की निगरानी और मूल्यांकन किया जा सके। यह प्रतिपूरक वनीकरण वन भूमि को दूसरे कार्यों जैसे खनन आदि में देने के बदले किया जाता है। जानकारों के मुताबिक, परिवेश वेबसाइट के आंकड़ों में अंतर इसलिए है क्योंकि इसमें मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ट्रांसफर वन भूमि को शामिल नहीं किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय 40 हेक्टेयर तक की वन भूमि गैर वन गतिविधियों के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में रिसर्चर कांची कोहली कहते हैं, मंत्रालय की दोनों वेबसाइट में वन भूमि के ट्रांसफर के आंकड़ों में समानता नहीं है। इसमें क्षेत्रीय कार्यालय के वन भूमि ट्रांसफर को शामिल नहीं किया गया है। आंकड़े स्पष्ट हों तो पता चलता रहता है कि नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। उदाहरण के लिए आंकड़ों से प्रतिपूरक वनीकरण व अन्य नियमों की जानकारी मिलती है लेकिन आंकड़ों की अस्पष्टता से इस पर नजर रखना संभव नहीं हो पाता।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008